राजपूत रुडा महा और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

5 दिसंबर, 1979

[एस.मुर्तजा फजल अली, पी.एस. कैलासम और ए.डी. कौशल, जेजे.]

उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 - धारा 2(ए) – दायरा - उच्चतम न्यायालय, यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के तहत एक अपील को संक्षेप में खारिज कर सकता है।

अपीलार्थी जिन पर हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया था सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त कर दिए गए। लेकिन राज्य की अपील पर, उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई। उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 की धारा 2(ए) के तहत अपील में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले और मामले में साक्ष्य के विस्तृत विश्लेषण के बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 384 के तहत अपील को संक्षेप में खारिज कर दिया।

निर्णय की घोषणा के बाद लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने से पहले, इस न्यायालय का ध्यान सीता राम बनाम यू.पी. राज्य [1979] 2 एस.सी.आर. 1085 के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया, जिसमे, उनके अनुसार, अभिनिर्धारित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास 1970 अधिनियम की धारा 2(ए) के तहत अपील में सीआरपीसी की धारा 384 के तहत अपील को संक्षेप में खारिज करने की कोई शक्ति नहीं थी। अपील को खारिज करते हुए -

अभिनिर्धारित किया : सीता राम बनाम यूपी राज्य मामले में निर्णय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के तहत किसी अपील को सरसरी तौर पर

खारिज करने की न्यायालय की शक्ति के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। उस मामले में न तो अतिरिक्त आधार जोड़ने के आवेदन में, न ही मामले को संविधान पीठ के समक्ष रखने का निर्देश देने वाले न्यायालय के आदेश में, धारा 384 की वैधता का कोई संदर्भ था और न ही यह दलील दी गई थी कि यह धारा संविधान के विपरीत थी। [356ई]

इसलिए न्यायालय की यह टिप्पणी कि उसने "इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया है" न्यायालय के लिए बाध्यकारी उदाहरण नहीं होगा। यह निर्णय इस प्रस्ताव का अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश XXI के नियम 15(1)(सी) को उस निर्णय में बताए अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। [356एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 718/1979

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 110/77 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11-10-1979 से उत्पन्न।

ए. के. त्रिवेदी और एस. एस. खांडुजा, अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

फ़ज़ल अली, न्यायाधिपति. –

सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ 1976 के सत्र मामले संख्या 46 में तीन अभियुक्तों द्वारा यह अपील की गई है।

तीनों अपीलार्थियों पर सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120-बी/323/324 सपठित धारा 34 और 109 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विचारण चलाया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने तीनों अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। गुजरात राज्य ने सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

दाण्डिक अपील सं. 110/77 में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्ति किये जाने के आदेश को उलट दिया और उन्हें धारा 302/120-बी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें कम अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया और कारावास की अलग-अलग शर्तों की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष ने तीन चश्मदीद गवाहों रत माला, गणेश और रूडा के साक्ष्य पर दृढ़ता से भरोसा किया। राता माला एक घायल प्रत्यक्षदर्शी थी जिसे कई चोटें लगी थीं। रूडा के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया। शिकायतकर्ता मृतक के भाई सवाई काला ने घटना के बाद के हिस्से को देखा जब मृतक को आरोपी ले जा रहा था। जब सवाई काला ने पूछताछ की, तो आरोपी ने उस पर हमला किया और वह भी घायल हो गया उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत फैसले में चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की पूरी तरह से जांच करने के बाद उनकी गवाही को स्वीकार कर लिया। इसने देखा कि चश्मदीद गवाह राता माला के साक्ष्य सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं और गणेश के साक्ष्य भी। उच्च न्यायालय ने उस परिस्थिति का उल्लेख किया है जिसके तहत इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को स्वीकार नहीं करने के लिए सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया। हमें भौतिक गवाहों के साक्ष्य द्वारा लिया गया है। हमें उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्तों को दोषमुक्ति के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारण पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अपील की याचिका की जांच करने के बाद और उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक हिस्सों को देखने के बाद, हम पाते हैं कि हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के तहत अपील को संक्षेप में खारिज कर दिया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के तहत अपील को सरसरी तौर पर खारिज करते हुए हमने अपना फैसला सुनाया, लेकिन फैसले पर हस्ताक्षर करने से पहले, इस न्यायालय का एक फैसला- सीता राम और अन्य बनाम यूपी राज्य [(1)] हमारे संज्ञान में लाया गया। जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के तहत किसी अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने की अदालतों की शक्ति के दायरे का उल्लेख किया गया है। उस मामले में उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 की धारा 2(ए) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 379 के तहत इस न्यायालय में अपील की गई थी। अपील को सर्वोच्च न्यायालय नियम 1966 के आदेश XXI नियम 15(1)(सी) के तहत प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अपीलार्थियों ने अतिरिक्त आधारों को प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया, अर्थात्, (1) उच्चतम न्यायालय के आदेश XXI नियम 15 के उप-नियम(1) के खंड (ग) के तहत प्रावधान जो न्यायालय को अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने का अधिकार देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के साथ असंगत होने के कारण अधिकार अधिकारातीत है। (2) संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को संसद के किसी अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों को निरस्त करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है और (3) सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 के तहत अपील को राज्य को नोटिस का आदेश देने वाले अभिलेखों को बुलाए बिना और बिना कारण बताए संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। जब अतिरिक्त आधार प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए याचिका न्यायालय के समक्ष आई, तो इस न्यायालय ने आदेश दियाः-

> "अपीलकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (ग) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो उस तरह की अपील को सक्षम बनाता है जिससे हम संबंधित हैं,

जिसे प्रवेश के लिए न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय सुनवाई के लिए रखा जा सकता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम सोचते हैं कि जब तक नियम की संवैधानिक वैधता का सवाल तय नहीं किया जाता है, तब तक हम भर्ती के लिए इस अपील की प्रारंभिक सुनवाई नहीं कर सकते। अतः अभिलेखों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ऐसा निर्देश देने के लिए रखा जाए जो उन्हें उचित और उपयुक्त लगे।"

यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया था क्योंकि उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XXI के नियम 15(1) के खंड (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। संवैधानिक वैधता के सवाल के साथ-साथ पहले उल्लिखित दो अन्य आधार भी उठाए गए थे। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अपील का अधिकार न्यायालय पर मामले के अभिलेख भेजने, दोनों पक्षों को सुनने और तर्कपूर्ण निर्णय लेने का दायित्व डालता है, न्यायालय के निर्णय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण इस प्रकार हैंः-

"अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि अपील का एक आत्यन्तिक अधिकार, जैसा कि उन्होंने इसका वर्णन किया है, न्यायालय पर मामले के रिकॉर्ड के लिए भेजने, दोनों पक्षों को सुनने और एक तर्कपूर्ण निर्णय देने का एक अपरिवर्तनीय दायित्व डालता है। इसलिए, प्रारंभिक पोस्टिंग अनुपस्थिति रिकॉर्ड पर एक सारांश सुनवाई द्वारा अपील को रद्द करना, एक पक्षीय और कारण देने से मुक्त होना निरंकुश होना है - वास्तव में, अनुच्छेद 134(1) में संविधान के विस्तार अधिनियम अधिनियम के अधिदेश के साथ असंगत स्थिति। अधिवक्ता का अप्रमाणिक दावे ने हमें आश्वस्त नहीं किया, लेकिन

हमने इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया है, जिसे संक्षेप में खारिज करने के लिए अनिच्छुक हैं।"

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के तहत अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने की न्यायालय की शक्ति के बारे में, विद्वान अधिवक्ता का निवेदन था कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होते हैं, जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था।

न तो अतिरिक्त आधार प्रस्तुत करने के आवेदन में या मामले को संविधान पीठ के समक्ष रखने के न्यायालय के आदेश में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 की वैधता का कोई संदर्भ था। न ही दलीलों के दौरान यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 संविधान के अधिकार अधिकारातीत है। चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 की वैधता का प्रश्न न तो उठाया गया था और न ही बहस की गई थी, इसलिए "इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने" के बाद न्यायालय द्वारा की गई चर्चा न्यायालयों के लिए एक पूर्ववर्ती बाध्यकारी नहीं होगी। निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के नियम XXI के नियम 15(1)(सी) को पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि निर्णय में संकेत दिया गया है।

हम ऊपर बताए गए कारणों से संतुष्ट हैं कि निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के दायरे के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने का आदेश कायम रहेगा।

पीबीआर.

याचिका खारिज की गई।

(1) [1979] 2 एस.सी.आर. 1085

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****